प्रादेशिक समाचार
आकाशवाणी जयपुर–अजमेर

दिनांक 25.05.2022 समय 18.30

- केन्द्र ने चीनी की घरेलू उपलब्धता और कीमतों पर नियंत्रण के लिए इसके निर्यात का नियमन करने का फैसला किया।

- केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह ने मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों को ऊर्जा संरक्षण के लिए संचालन समिति गठित करने को कहा।

- लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा –युवाओं की ऊर्जा और विश्वास नये भारत के निर्माण का आधार है।

- मुख्य सचिव ने सुव्यवस्थित भेड़ निष्क्रमण के लिए अधिकारियों को पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

- प्रदेश में माहवारी स्वच्छता जागरूकता विशेष अभियान कल से।

0000

केन्द्र सरकार ने चीनी की घरेलू उपलब्धता और कीमतों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए चीनी निर्यात का नियमन करने का फैसला किया है। चीनी के निर्यात के लिये एक करोड़ मीट्रिक टन की सीमा तय की गई है। चीनी निर्यात की यह सीमा इस वर्ष पहली जून से 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को इस बारे में जानकारी देते हुए खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा कि चीनी मिलों और निर्यातकों को चीनी निर्यात के लिये खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के संबंधित निदेशालय से अनुमति लेना जरूरी होगा। उन्होंने बताया कि इस मौसम में भारत से निर्यात रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पहुंच गया है और अक्टूबर, नवम्बर में त्यौहारी मौसम के दौरान चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को स्थिर रखने के लिये संकल्पित है और पिछले 12 महीनों में चीनी की कीमतें नियंत्रण में हैं।

0000

केन्द्र ने प्रति वर्ष बीस लाख मीट्रिक टन कच्चा सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है। सीमा शुल्क तथा कृषि बुनियादी ढांचा और विकास उपकर की शून्य दर पर आयात की यह अनुमति दो वर्ष तक जारी रहेगी। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में बताया कि शुल्क मुक्त आयात वित्तीय वर्ष 2022–23 और 2023–24 के लिए लागू होगा। इस रियायत से तेल की घरेलू कीमतें कम करने और मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण में मदद मिलेगी।

0000

ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह ने सभी मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों को ऊर्जा संरक्षण के लिए राज्यस्तरीय संचालन समिति गठित करने को कहा है। ये संचालन समितियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में काम करेंगी। श्री सिंह ने कहा कि सबसे अधिक ऊर्जा दक्ष रूप से सतत विकास पर राज्य–विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर की गई अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का एकमात्र साधन ऊर्जा संरक्षण है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे कुछ राज्यों ने पहले ही ऐसी समितियों का गठन कर लिया है। श्री सिंह ने राज्यों से कृषि क्षेत्र में डीजल के उपयोग को सीमित करके वर्ष 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल उपयोग के स्तर को शून्य करने के लिए प्रयास करने का आग्रह किया है।

0000

लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सम्पूर्ण विश्व देश के युवाओं को आशाभरी नजरों से देखता है और उनकी ऊर्जा और विश्वास भी नये भारत के निर्माण का आधार है। श्री बिरला ने आज जयपुर में 'युवा उद्यमी संवाद' कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं से देश, संसद, समाज, राजनीति और चुनौतियों के साथ आ रहे बदलावो सहित विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा की। श्री बिरला ने कहा कि संवाद के दौरान एक बार फिर युवाओं में देश को नवनिर्माण की दिशा में ले जाने वाली सकारात्मकता और उद्यमशीलता दिखाई दी।

लोकसभा अध्यक्ष ने अधिक से अधिक युवाओं को राजनीति में आने को कहा है। उन्होंने कहा कि लेकिन इस क्षेत्र में आकर मेहनत और मानवता की सेवा करनी चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि राजनीति में अनिश्चिता है, लेकिन जो लोग बिना किसी पद की लालसा के मेहनत करते हैं उन्हें जनता का स्नेह भी मिलता है। श्री बिरला ने एक अन्य कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित भी किया।

00000

प्रदेश में निवेश, उद्योगों की स्थापना और जापानी कंपनियों को नीमराणा में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जापान एक्सटर्नल ट्रेड आर्गनाइजेशन जेट्रो और नाइडेक कंपनी के उच्चाधिकारियों ने आज जयपुर में अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता और रीको के अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि जापानी कंपनियों ने प्रदेश में निवेश को बढ़ाया है। उन्होंने

इन कंपनियों से अक्टूबर में होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान समिट में भी सहयोग का आग्रह किया। रीको की प्रबंध निदेशक अर्चना सिंह ने बताया कि नीमराणा में राज्य सरकार जापानी कंपनियों को निवेश का बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के लिए सभी जरूरी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।

00000

आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध को बढ़ावा देने के लिये माउंटआबू की आंतरिक सुरक्षा अकादमी और जोधपुर के सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के बीच एम. ओ. यू. किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र की मौजूदगी में आज माउंटआबू में अकादमी के निदेशक और महानिरीक्षक एम. एस. शेखावत और सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. आलोक त्रिपाठी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। राज्यपाल ने इस करार को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे देश में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से सैद्धांतिक के साथ व्यावहारिक प्रयासों को गति मिलेगी। श्री मिश्र ने आंतरिक सुरक्षा अकादमी का दौरा किया। उन्होंने अकादमी के अधिकारियों से इसकी कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा की। उन्होंने आंतरिक सुरक्षा की वर्तमान चुनौतियों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समयानुरूप बनाए जाने की आवश्यकता जताई।

00000

प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन का बीकानेर तक विस्तार किया गया है। ट्रेन को चूरू के सांसद राहुल कस्वां ने झंडी दिखाकर रवाना किया। केन्द्रीय मंत्री और बीकानेर से सांसद अर्जुनराम मेघवाल और शिक्षा मंत्री डॉ बी डी कल्ला वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। सांसद कस्वां ने कहा कि प्रयागराज से जयपुर ट्रेन के चुरू होते हुए बीकानेर तक विस्तार से इस क्षेत्र को बहुत फायदा होगा। सीकर में सांसद सुमेधानंद ने झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। अब ये ट्रेन सप्ताह में 4 दिन वाया सीकर–फतेहपुर शेखावाटी–चूरू, और सप्ताह में तीन दिन वाया सीकर–झुंझुंनू–लोहारू–सादुलपुर–चूरू होकर चलेगी।

00000

राज्य में सुव्यवस्थित भेड़ निष्क्रमण के लिए मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने अधिकारियों को जिलों में पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने निर्बाध भेड़ निष्क्रमण के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए है। मुख्य सचिव आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से भेड़ निष्क्रमण की पूर्व तैयारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। उन्होंने कहा कि कई बार पशुपालकों की भेड़ उनके रास्ते में पड़ने वाले किसानों के खेतों में घुस जाती हैं, जिससे उनमें और भेड़ पालकों में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। श्रीमती शर्मा ने कहा कि इस स्थिति से बचने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन पहले से ही सचेत होकर काम करें। साथ ही निर्धारित मार्ग से ही भेड निष्क्रमण सुनिश्चित करें। मार्ग में फेरबदल की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई करते हुए सुगम निष्क्रमण को सुनिश्चित करें।

00000

रणथंभौर बाघ परियोजना की खंडार रेंज में बाघिन टी–69 के डेढ वर्ष के मादा शावक की मौत हो गई है। नियमित गश्त के दौरान इसका शव वनकर्मियों को गोठ बिहारी के पास नीला पट्टा वन क्षेत्र में मिला। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार शावक के शरीर पर घाव मिले हैं। संभवतः अन्य बाघ से शिकार के लिये हुए संघर्ष में इसकी मौत हुई है। अधिकारियों का कहना है कि मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। 13 मई को भी इस टाइगर रिजर्व में एक बाघिन की मौत हो गई थी।

00000

प्रदेश में 28 मई को आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय माहवारी स्वछता दिवस से पहले माहवारी के बारे में महिलाओं को जागरूक किया जायेगा। इसके लिये कल और परसों विशेष अभियान चलाया जायेगा। इसी सिलसिले में आज जयपुर में इस विषय पर एक दिन की कार्यशाला आयोजित की गयी। कार्यशाला में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने माहवारी के दौरान सफाई के बारे में जागरूकता पोस्टर जारी किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में श्रीमती भूपेश ने बताया कि समाज के लिए माहवारी स्वच्छता एक जरूरी मुद्दा है। सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए आईएम शक्ति उडान योजना शुरू की है, जिसके तहत सैनेटरी नैपकिन मुफ्त में वितरित किये जा रहे है।

00000

प्रदेश में कई स्थानों पर वर्षा, आंधी और तेज हवाओं के कारण गर्मी का असर कम हुआ है। ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सैल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है। आज झालावाड़ में हल्की वर्षा हुई। कुछ अन्य जिलों में भी बूंदाबांदी के समाचार हैं। मौसम विभाग ने आज अजमेर, अलवर, भरतपुर, बूंदी, बारां, कोटा, धौलपुर, करौली, टोंक तथा सवाईमाधोपुर में तेज हवाएं चलने तथा बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गयी है। विभाग के अनुसार अगले तीन दिन कहीं–कहीं वर्षा और तेज हवा चलने का दौर जारी रहेगा।

00000

बूंदी जिले के अभयपुरा, भीमलत और बरधा बांध क्षेत्र के 41 गांवों के किसानों को फार्म पौंड, डिग्गी बनाने और पाईप लाईन डालने पर अनुदान दिया जायेगा। उपनिदेशक कृषि विस्तार रमेश चंद जैन ने बताया कि फार्म पौंड के लिये लागत का 75 प्रतिशत या 1 लाख 12 हजार 500 रुपये अनुदान के रूप में दिये जायेंगे। इस तरह डिग्गी बनाने पर लागत का 75 प्रतिशत या 3 लाख रुपये और पाइप लाइन पर लागत का 75 प्रतिशत या साढे 22 हजार रुपये का अधिकतम अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसान इस योजना का लाभ लेने के लिये कृषि विभाग में आवेदन कर सकते हैं।

00000